मुख्यमंत्री भजनलाल ने योगाभ्यास किया

मुख्यमंत्री निवास पर हुए कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के पदाधिकारी व आर.ए.सी. के जवानों ने भी भाग लिया

जयपुर, 18 जून। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान के पदाधिकारियों एवं आरएसी जवानों के साथ योग एवं प्राणायाम अभ्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील की।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान के पदाधिकारियों एवं आरएसी जवानों के साथ योग एवं प्राणायाम अभ्यास किया।

कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की एक प्रभावी जीवनशैली है। उन्होंने नियमित योगाभ्यास को मानसिक शांति, शारीरिक सुदृढ़ ता और आत्मिक संतुलन का आधार बताते हुए प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया गया। इस दौरान क्रीड़ा भारती राजस्थान के पदाधिकारी, आरएसी के जवान तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

अमेरिकी राजदूत ने अमित शाह से मुलाकात की

नई दिल्ली, 18 जून। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां मुलाकात की तथा दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बताया कि

- **मुलाकात में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा हुई।**

उन्होंने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच बढ़ ते द्विपक्षीय संबंधों का लाभ भारत और अमेरिका के नागरिकों को मिलेगा।

राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस का प्रत्याशी हारा

कांग्रेस के दो तथा भाजपा का एक वोट रद्द हुआ, राजद व भाकपा (माले) पर क्रॉस वोटिंग के आरोप

रांची, 18 जून। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस के दो और बीजेपी का एक वोट रद्द हो गया, जबकि राजद और भाकपा माले के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। मतगणना के बाद झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को विजयी घोषित किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को केवल 19 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में निराशा का माहौल दिखा। मतगणना स्थल से कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, प्रत्याशी प्रणव झा समेत कई मंत्री और विधायक बाहर निकल गए।

- **मतगणना के बाद झामुमो के वैद्यनाथ राम तथा एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी विजयी घोषित हुए।**

कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने कहा कि "कांग्रेस के सभी 16 वोट सुरक्षित हैं। झामुमो ने चार वोट दिए और कांग्रेस को 20 वोट मिले। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ने पैसे का इस्तेमाल किया।"

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद और शर्मनाक घटना है।

'रामगोपाल यादव के नेतृत्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर पहले आंतरिक संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्य रूप से भाजपा के खिलाफ प्रमुख चुनौतीकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हालांकि यह संभव है कि चुनाव के अंतिम चरणों में टिकट न मिलने या अन्य कारणों से असंतोष रखने वाले कुछ व्यक्तियों में नाराजगी दिखाई दे, लेकिन अखिलेश ने पार्टीजनों में अपनी स्थितित काफी मजबूत कर ली है, और मौजूदा स्थिति में बड़े पैमाने पर दलबदल की संभावना बहुत कम मानी जा रही है।

फिर भी, भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकता है, जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना, संदेह पैदा करना और अस्थिर तत्वों को प्रभावित करना। इन बढ़ी हुई अफवाहों का उद्देश्य सपा की स्थिरता के बारे में सन्देह पैदा करके, समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के बीच भी दरार पैदा करना हो सकता है, ताकि विपक्षी दलों के बीच भरोसा कमजोर हो और अन्य गैर-भाजपा समूह मजबूत गठबंधन बनाने में हिचकिचाएं।

नीट री-एग्ज़ाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब वहां से बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों तक भेजा जाएगा। इस मामले में संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, ताकि बिना किसी देरी के और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से प्रश्नपत्र तय समय पर सही जगह पहुंच सकें और गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। गौरतलब है कि इससे पहले 3 मई को हुई नीट-यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और धांधली के आरोप लगे थे।

शिवसेना के सांसदों ने बड़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिछले 48 घंटों में गुप्त बैठकों और देर रात दिल्ली की उड़ानों के जरिए अंजाम दी गई।

यह पूरा घटनाक्रम 16 जून की आधी रात से शुरू हुआ, जब ये सांसद विभिन्न राज्यों से निजी चार्टर्ड विमानों से गुपचुप दिल्ली पहुंचे।

16 जून को रात के डेढ़ बजे नांदेड से निजी विमान द्वारा नरेश पाटिल अश्तिकार दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। देर रात सांसद संजय देशमुख और संजय बंडू जाधव भी एक अन्य निजी विमान से दिल्ली आ गए। मध्यरात्रि के ही समय भाऊसाहेब वाकचौरे हैदराबाद से प्राइवेट जेट द्वारा दिल्ली पहुंचे और रात को ही, सांसद संजय दिना पाटिल और विधायक प्रताप सरनाइक भी दिल्ली पहुंच गए।

इसी दौरान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 17 जून को रात के लगभग 3:00 बजे जयपुर से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद 4:30 बजे सांसद श्रीकांत शिंदे (एकनाथ शिंदे के पुत्र) और बागी सांसद ओमराजे निंबालकर पुणे से दिल्ली पहुंचे। सभी छह असंतुष्ट सांसदों को, आगमन के तुरंत बाद, नोएडा के एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

17 जून की सुबह राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं और मामला व्यक्तिगत बैठकों से आगे बढ़कर संसदीय प्रक्रिया तक पहुंच गया।

सुबह 7 बजे श्रीकांत शिंदे और ओमराजे निंबालकर ने सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात की। फिर दस बजकर 20 मिनट पर ओमराजे निंबालकर के नेतृत्व में पांच सांसदों का समूह विस्तृत चर्चा के लिए स्पीकर के कार्यालय पहुंचा।

- **अब ये सभी 6 बागी सांसद 20 जून को एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे, उसके बाद पत्रकारों के सामने दलबदल के कारणों का खुलासा करेंगे।**

बताया जाता है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में छह सांसदों ने एक हस्ताक्षरित प्रस्ताव स्पीकर को सौंपा। रिपोर्ट्स के अनुसार, पत्र में कहा गया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना "अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है।" इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं।

विचारधारा में बदलाव का हवाला देते हुए, सांसदों ने आधिकारिक रूप से उन्हें शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसदों के रुप में मान्यता देने की मांग की।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, ये सांसद अलग-अलग स्थानों पर लौट गए, ताकि दल-बदल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक वे नज़रों से दूर रह सकें।

नरेश अश्तिकार चेन्नई के रास्ते तिरुपति गए और भाऊसाहेब वाकचौरे वाराणसी पहुंचे। तथा संजय देशमुख और संजय जाधव अयोध्या चले गए। वहीं, बाकी दो सदस्य, संजय दिना पाटिल और ओमराजे निंबालकर, मुंबई और पुणे लौट गए।

सूत्रों के अनुसार, ये छह बागी सांसद 20 जून को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में वे मीडिया से भी रूबरू होंगे और अपने दलबदल के कारण बताएंगे।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कराए जाएंगें। इन विकास कार्यों से मण्डियों में किसानों और व्यापारियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि उपज मण्डी समितियों से जुड़ी संपर्क सड़कों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की मरम्मत से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी उपज सुगमता से मण्डी तक ला सकेंगे। इससे मण्डियों में फसलों की आवक बढ़ गी, किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी तथा मण्डी राजस्व में भी वृद्धि होगी।

क्या नेतन्याहू यूएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ा, वहीं, शांति समझौते की बातचीत में तेल अवीव को लगभग बाहर रखा गया। और इस तथ्य ने, कि ट्रंप ने मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को चुना, स्थिति को और जटिल बना दिया। सच्चाई यह है कि नेतन्याहू ने इस युद्ध पर अपना सब कुछ दांव लगा दिया था। अमेरिका-ईरान अंतरिम समझौते ने इज़रायल के कई लक्ष्यों को अधूरा छोड़ दिया है और नेतन्याहू को ट्रंप से भी दूर कर दिया है।

ट्रंप और नेतन्याहू के संबंध भी अब पहले जैसे नहीं रहे, जब फरवरी में नेतन्याहू वाइट हाउस पहुंचे थे और ईरान पर हमले की योजना पेश की थी और ट्रंप उससे तुरन्त प्रभावित हो गये थे। इस समझौते में इज़रायली प्रधानमंत्री को ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई, जिसे चार महीने बाद होने वाले चुनावों में वे जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। ईरान पर हमला और उसके सहयोगियों, जैसे हिज़्बुल्लाह,को कमजोर करना नेतन्याहू का दशकों पुराना लक्ष्य रहा है। उन्होंने हमेशा ईरान और उसके सहयोगियों को इज़रायल और मध्य पूर्व के लिए बड़ा खतरा बताया है। लेकिन उन्हें वाइट हाउस में इस विचार वाला साझेदार नहीं मिला। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू ने एक अवसर देखा और 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमला कर दिया।

लेकिन हालात तब उलट गए, जब ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर दिया। अमेरिका में आर्थिक दबाव बढ़ने लगा और ट्रंप की लोकप्रियता भी गिरने लगी। अंतत: सीमित विकल्पों के चलते ट्रंप ने इज़रायल की राय के बिना ही जल्दबाज़ी में एक समझौता कर लिया।

नतीजा यह रहा कि अमेरिका और इज़रायल अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए। ईरान की धार्मिक सत्ता अब भी मौजूद है, और उसका उच्च-स्तरीय संवर्धित यूरेनियम भंडार , जो परमाणु - हथियार बनाने में काम आने वाला प्रमुख तत्व है, भी अभी देश के भीतर मौजूद है। इसके अलावा, ट्रंप ने यू-टर्न लेते हुये यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम छोड़ने के लिये दबाव नहीं डालेगा।

महाराष्ट्र सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिवसेना यूबीटी की ओर से आज दिल्ली में सभी नौ सांसदों की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इनमें से सिर्फ तीन सांसद उपस्थित थे। इसके बाद इन सभी छह बागी सांसदों को पार्टी की ओर से सात दिन का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि शिवसेना शिंदे समूह के एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के सभी छह बागी सांसद उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं।

तृणमूल का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हजारों फुटबॉल प्रशंसकों, जिनमें अधिकतर युवा थे, ने लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए भारी रकम चुकाई थी। लेकिन अरूप बिस्वास ने दादागिरी से सभी टिकट धारकों को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया।

इस अव्यवस्था और वास्तविक टिकट धारकों को बाहर किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। टिकट धारकों ने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ।

बताया जाता है कि अरूप बिस्वास ने बार-बार मेसी के साथ तस्वीरें लेने के लिए उन्हें गले लगाया और उनके साथ अत्यधिक निकटता दिखाई। बाद में जब स्थिति और बिगड़ गई, तब मेसी को अव्यवस्था के बीच स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी पूर्व खेल मंत्री के व्यवहार पर प्रतिकूल टिप्पणी की और पूछा कि क्या अरूप बिस्वास मेसी के बचपन के मित्र हैं कि वे बार-बार उन्हें इस तरह गले लगा रहे थे और कमर से पकड़ रहे थे।

बिस्वास ने एचडीएफसी बैंक की शाखा को पार्टी खाते फ्रीज़ करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने स्वयं को पार्टी का कोषाध्यक्ष बताते हुए पत्र पर हस्ताक्षर किए और कहा कि पार्टी इस समय गंभीर उथल-पुथल से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्ष पार्टी फंड पर दावा कर रहे हैं। हालांकि, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी विधायकों ने कहा है कि अरूप बिस्वास पार्टी फंड पर अपना नियंत्रण कायम रखने की कोशिश में जुटे हैं।

होर्मुज़ में 13 भारतीय जहाज अभी भी फंसे हुए हैं

नई दिल्ली, 18 जून। युद्ध समाप्ति की घोषणा होने के तीन दिन बाद और 17 जून 2026 को अमेरिका व ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते के बावजूद, यह साफ नहीं है कि हॉर्मुज़ में फंसे 13 भारतीय जहाज वहां से कब वापस निकलेंगे।

- **युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद केवल एक भारतीय जहाज 'दिशा' बाहर निकल पाया है।**

पिछले चार दिनों में हॉर्मुज़ से एलएनजी शिपिंग जहाज "दिशा" के अलावा कोई भी भारतीय जहाज बाहर नहीं निकल सका है। दिशा 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी ले कर शुक्रवार (19 जून) को गुजरात के दहेज पोर्ट पर पहुंचने की पूरी संभावना है। लेकिन सरकारी अधिकारियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अन्य भारतीय जहाज वहां से कब निकलेंगे, इससे चिंता बनी हुई है। 13 भारतीय जहाजों के अलावा, पश्चिम एशिया के अन्य समुद्री क्षेत्रों में भारत के लिए तेल-गैस-उर्वरक ले कर आने वाले करीब 20 अन्य जहाज भी फंसे पड़े हैं। सरकार पूरे मामले में सक्रिय है।

जहाजरानी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ तथा अन्य स्थानों से सुरक्षित निकालने के लिए विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष की शुरुआत इस साल फरवरी के अंत में हुई थी। उस समय होर्मुज तथा पर्शियन गल्फ क्षेत्र में 22 से 38 भारतीय ध्वज वाले या भारत के लिए माल से लदे जहाज फंसे हुए थे, जिन पर सैकड़ों भारतीय नाविक सवार थे।

पाकिस्तान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना राज्य प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हस्तक्षेप कर पाकिस्तान सरकार को जवाबदेह ठहराने की मांग की। चुग ने गुरुवार को जारी बयान में इस हत्या को बर्बर और बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस हमले से पाकिस्तान में रहने वाले सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा सरकार से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

ईरान की मांग ने ट्रंप के दावों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनकी यह टिप्पणी ट्रंप के उस दावे को सीधे चुनौती देती है, जिसे उन्होंने केवल एक दिन पहले जी-7 शिखर सम्मेलन में दोहराया थी कि 60 दिन की वार्ता अवधि के बाद भी यह समुद्री मार्ग बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा।

यह मतभेद तकनीकी लग सकता है, लेकिन समझौते को लेकर दोनों पक्षों की अलग-अलग कहानियों के मूल में यही है।

तेहरान के लिए, जहाजों से शुल्क वसूलने की क्षमता का मतलब होगा, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर ईरान के प्रभाव की औपचारिक मान्यता मिलना। वहीं वॉशिंगटन के लिए ऐसी व्यवस्था स्वीकार करना 100 दिनों से अधिक चले सैन्य संघर्ष के बाद पीछे हटने जैसा माना जा सकता है।

गालिबाफ ने इससे भी आगे बढ़ते हुए, एमओयू को "अमेरिकी विफलता का रिकॉर्ड" बताया और कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने अंतत: होर्मुज़ को बाधित करने की ईरान की लंबे समय से चली आ रही धमकी को वार्ता के एक ठोस हथियार में बदल दिया है। इस घोषणा का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक ऊर्जा बाजार तनाव कम होने के संकेतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगे थे।

समझौते के कुछ ही घंटों बाद छह मिलियन बैरल कच्चा तेल ले जा रहे सऊदी अरब के तीन सुपरटैंकर जलडमरूमध्य से गुजर गए। संघर्ष के दौरान अपनी गतिविधियाँ छिपाने वाले अन्य जहाजों ने भी फिर से खुले तौर पर अपनी स्थिति को खुले तौर पर बताना शुरू कर दिया।

ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि होर्मुज़ के फिर से खुलने से खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों पर फँसे लगभग 9 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति बाजार में आ सकती है, जिससे वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। यदि प्रतिबंधों में और राहत मिलती है तो अतिरिक्त ईरानी निर्यात आपूर्ति को और बढ़ा सकते हैं।

फिर भी होर्मुज़ विवाद ट्रंप प्रशासन के खिलाफ उठ रही एक बड़ी आलोचना को भी मजबूत करता है कि यह युद्ध उन बड़े लक्ष्यों की तुलना में कहीं अधिक सीमित परिणामों के साथ समाप्त हुआ है, जिनका वादा शुरू में किया गया था।

ट्रंप के तथाकथित शांति समझौते का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिर भी जितनी जानकारी सामने आई है, वह कई कठिन सवाल खड़े करती है।

अंतत: युद्धों का मूल्यांकन भाषणों से नहीं, बल्कि परिणामों से किया जाता है। आलोचकों का कहना है कि यदि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के समय ट्रंप द्वारा घोषित लक्ष्यों की तुलना उभरते हुए समझौते की रूपरेखा से की जाए, तो वॉशिंगटन को उसकी मूल मांगों की तुलना में बहुत कम हासिल हुआ है।

जब संघर्ष शुरू हुआ था, तब प्रशासन के लक्ष्य काफी व्यापक दिखाई देते थे। इनमें ईरान की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को समाप्त करना, उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पंगु बनाना, उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कमज़ोर करना, होर्मुज़ में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करना और कुछ हलकों में तेहरान में सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा देना भी शामिल था। चार महीने बाद तस्वीर कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। कथित रूप से, ईरान ने परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे न बढ़ने और बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है, लेकिन उसकी परमाणु संरचना को तुरंत समाप्त करने या संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाने जैसी कोई बात नहीं हुई है। सबसे विवादास्पद मुद्दों को भविष्य की वार्ताओं के लिए टाल दिया गया है।

सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य भी लगभग समाप्त हो गया है। संघर्ष के दौरान भारी सैन्य नुकसान झेलने के बावजूद, इस्लामी गणराज्य की सरकार सत्ता में मजबूती से बनी हुई है। ईरान का राजनीतिक नेतृत्व अमेरिका और इज़रायल के सीधे सैन्य अभियान से बच गया और संभव है कि घरेलू स्तर पर उसकी स्थिति और मजबूत हो जाए।

शायद सबसे तीखी आलोचना बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर है।

ट्रंप ने ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करने का वादा करते हुए युद्ध शुरू किया था। लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, बाद में उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें न होना अनुचित होगा। यह रुख प्रशासन के, युद्ध के शुरुआती लक्ष्यों से काफी अलग है। आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका अंतत: केवल पहले जैसी स्थिति बहाल करने के लिए भारी राजनीतिक कीमत चुका सकता है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य फिर से खुल रहा है। प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। परमाणु वार्ताएँ दोबारा शुरू हो रही हैं। लेकिन ये सभी मुद्दे युद्ध शुरू होने से पहले भी कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा थे।

होर्मुज़ शुल्क विवाद ने इस आलोचना को और तेज कर दिया है। यदि ईरान अंतत: जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर शुल्क लगाने में सफल हो जाता है, तो तेहरान यह दावा कर सकेगा कि वह युद्ध से पहले की तुलना में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति लाइन पर अधिक नियंत्रण (लीवरेज) के साथ इस युद्ध से बाहर निकला है।

एक और सवाल प्रभाव और दबाव की क्षमता का भी है।

कई विश्लेषकों का तर्क है कि होर्मुज़ के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित करने की ईरान की क्षमता ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर भारी आर्थिक दबाव बनाया। तेल कीमतों में बढ़ोतरी और व्यापक आर्थिक झटके की आशंका के कारण अमेरिका शायद अपेक्षा से कमजोर स्थिति में बातचीत करने को मजबूर हुआ।

ट्रंप के समर्थक इस व्याख्या को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ईरान की सैन्य संरचना को भारी नुकसान पहुँचा, उसके मिसाइल भंडार का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, उसकी वायु रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ गई और उसकी अर्थव्यवस्था संकट के कगार पर पहुँच गई।

उनके अनुसार, तेहरान केवल इसलिए बातचीत की मेज पर लौटा, क्योंकि लगातार सैन्य दबाव के कारण उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। हालाँकि आलोचक इससे सहमत नहीं हैं। उनका मुख्य आरोप सरल है: अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत कई मोर्चों पर आत्मसमर्पण की मांग के साथ की थी, लेकिन अब वह युद्धविराम, भविष्य की वार्ताओं और ईरानी आश्वासनों पर ही समझौता करने को तैयार है।

इसलिए गालिबाफ की घोषणा का महत्व केवल समुद्री शुल्क तक सीमित नहीं है। इसने ट्रंप और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर मूल बहस को फिर से जीवित कर दिया है-क्या यह ताकत के दम पर हासिल की गई स्थाई शांति है, या एक महंगा समझौता है, जो उन उद्देश्यों को पूरा करने में काफी पीछे रह गया है, जिनके लिए युद्ध लड़ा गया था। अगले 60 दिनों तक चलने वाली वार्ताओं के दौरान इसका उत्तर शायद यह तय करेगा कि इतिहास इस समझौते को एक शानदार कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में याद रखेगा या ऐसी जीत के रूप में, जिसकी घोषणा वॉशिंगटन में हुई, लेकिन जिसकी व्याख्या तेहरान में बिल्कुल अलग तरीके से की गई।

सरकार पहल करके पाँचना बाँध विवाद का हल निकाले- पायलट

उन्होंने कहा, सभी पक्षों को विश्वास में लेकर बातचीत करें व न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करें

जयपुर, 18 जून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि पांचना बांध विवाद के समाधान के लिए राज्य सरकार को तत्काल पहल करते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित करना चाहिए तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी सभी की आवश्यकता है और किसी भी परिस्थिति में तनाव तथा भाईचारे में खटास की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

- **पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि देश के 14-15 राज्यों में एसआई भर्ती में इन्टरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। राजस्थान में भी इन्टरव्यू प्रणाली समाप्त करके केवल मैरिट आधारित चयन प्रक्रिया लागू करनी चाहिए।**

पायलट ने कहा कि लंबे समय से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है और इस विषय से जुड़े विभिन्न पक्षों की अपनी-अपनी चिंताएं और मांगें हैं। नदी किनारे स्थित 360 गांवों के किसानों का भी अपना पक्ष है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी पक्षों को विश्वास में लेकर बातचीत करे और न्यायपालिका के निर्णयों का सम्मान करते हुए समाधान का रास्ता निकाले।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए।

पायलट ने कहा कि हाल ही में कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हजारों विद्यार्थियों के बीच जो बातें रखीं, उससे उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े गंभीर सवालों को देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं, कोचिंग व्यवस्था और निजी संस्थानों का सबसे अधिक बोझ मध्यमवर्गीय और ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है।

पायलट ने कहा कि पिछले वर्षों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। परीक्षा होने के बाद प्रश्नों को हटाने, मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी और नई-नई प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा को लेकर पायलट ने कहा कि देश के लगभग 14-15 राज्यों में एसआई भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उन्होंने मांग की कि राजस्थान सरकार को भी एसआई भर्ती में इंटरव्यू प्रणाली समाप्त कर केवल मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया लागू करनी चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं का विश्वास कायम रह सके।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908